रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड रक्षा सेवाओं के लिए उनसे प्राप्त विशिष्ट आर्डरों अथवा उनके द्वारा बताई गई पक्की आवश्यकताओं के प्रति इलैक्ट्रानिक उपस्कर तैयार कर रहा है। इलैक्ट्रानिक उपस्करों की कुछ मदों के लिए रक्षा आवश्यकताएं देश में कुछ अन्य यूनिटों द्वारा भी पूरी की जाती हैं, जैसे हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का हैदराबाद प्रभाग; इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, और इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज आदि। इस समय भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की सीमा में पड़ने वाले उपस्करों की किस्मों का इस समय जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है उसके अनुसार बंगलौर और गाजियाबाद की भारत इलैक्ट्रानिक्स यूनिटों में उपलब्ध उत्पादन क्षमता अथवा स्थापित की जा रही क्षमता, कुल मिला कर, रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट के कारखाने का निर्माण प्रगति पर है। तथापि, इस यूनिट ने सितम्बर, 1973 से उत्पादन पहले ही आरम्भ कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Grant of Passports to Shri Ashok Solomon involved in criminal cases

4698. SHRI B. R. SHUKLA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Shri Ashok Solomon who was recently arrested in Delhi in connection with hashish case, managed to secure passports to go abroad four times since 1968 although he was on bail in connection with some criminal cases pending against him; and

(b) if so, the reasons for permitting him to leave India during the pendency of investigation for trial against him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and (b). It is not true that Shri Ashok Solomon has been given passport facilities to travel abroad *after* his involvement in a criminal case was brought to our notice by the Delhi police authorities on 15-11-1973.

The facts of the case are that Shri Solomon had applied and received an Indian passport in July, 1968 on the basis of a duly verified passport application which was complete in every respect. Shri Solomon subsequently in July, 1971, applied for the renewal of his passport and since there was nothing adverse against him his passport was renewed till July, 1974 (final).

Now that Shri Solomon's involvement in a criminal case has been brought to our notice by the Delhi police authorities, we have issued necessary instructions to all authorities concerned that he should not be given any passport facilities without prior clearance from this Ministry.

रानीगंज और झरिया कोयला खानों के विभिन्न ग्रेडों में कोयले के मूल्य

4699. श्री अवधेश चन्द्र सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज और झरिया कोयला खानों में स्लेक के जो ईंट के भट्टों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, विभिन्न ग्रेडों के मूल्य क्या हैं, और उन कोयला खानों के अधिग्रहण से पूर्व इन के मूल्य क्या थे ; और

(ख) वर्ष 1972-73 में कितना उत्पादन तथा लदान हुआ तथा पूर्व वर्ष में कितना-कितना हुआ था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) गैर कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व और बाद,

बंगाल–बिहार के कोयला क्षेत्र के विभिन्न ग्रेड के कोयला चूर्ण के गर्त-मुख मूल्य नीचे दिए गए है :—

	रुपये प्रति टन
बढ़िया 'क'	47.00
बढ़िया 'ख'	42.00
ग्रेड i	39.00
ग्रेड ii	35.00
ग्रेड iiiक	32.62
ग्रेड iiiख	31.45

(ख) गैर-कोककारी कोयला खानों का जनवरी, 1973 में प्रबन्ध ग्रहण किया गया। 1973 और 1972 को प्रत्येक वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान बंगाल और बिहार में उत्पादित और प्रेषित गैर-कोककारी कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है।

	उत्पादन		प्रेषण	
	1972	1973	1972	1973
	(अनुमानित)			
				लाख टनों में
बंगाल	147.00	153.50	139.50	150.00
बिहार	141.60	150.00	110.00	100.70

हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में आदेशों को जारी किया जाना

4700. **श्री सुधाकर पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में सभी सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हों ;

(ख) पिछली तिमाही में ऐसे कितने मामले सामने आये है ; जिनमें मंत्रालय अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों ने सामान्य आदेश की श्रेणी में आने वाले पत्र, परिपत्र और ज्ञापन आदि केवल अंग्रेजी में जारी किए और उनका हिन्दी रूपान्तर साथ में जारी नहीं किया; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (ग): रक्षा संगठन में सामान्य आदेशों को उपलब्ध साधनों की सहायता से यथा संभव रूप में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जा रहा है। तथापि यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पर्याप्त अनुवाद कर्मचारी और मुद्रण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

राज भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

4701. **श्री सुधाकर पांडेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अनेक अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन